साप्ताहिक

डाक पंजीयनः म.प्र./भोपाल/4-479/2019-21

RNI-MPHIN/2015/72544

# जागत गांव हमार

पंचायत की विकास गाथा, सरकार तक

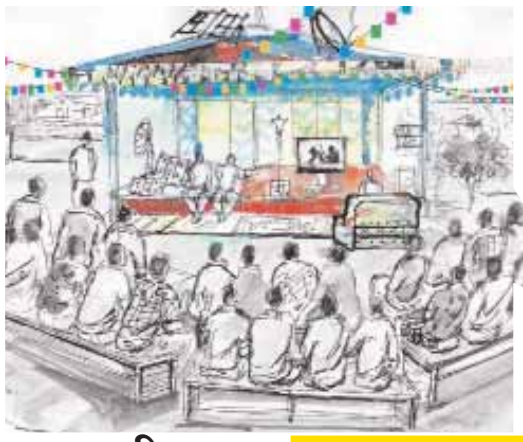

चौपाल से भोपाल तक

भोपाल, सोमवार, 23 अगस्त 2021, वर्ष-7, अंक-21

भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर, मुरैना से एक साथ प्रकाशित

पृष्ठ :-8, मूल्य :- 8 रुपए

» रीवा जिले के रकरी गांव के प्रगतिशील किसान धर्मजय का चेन्नई में चल रहा इलाल

» चार माह में दो करोड़ इलाज में हो चुके खर्च, फेंफड़ा 95 प्रतिशत हो गया संक्रमित

» बेटे ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह से मांगी आर्थिक मदद

# कोरोना से जिंदगी की जंग लड़ रहे किसान की सरकार से मदद की गुहार

संवाददाता, भोपाल/रीवा

कोरोना से जिंदगी की जंग लड़ रहे मप्र के प्रगतिशील किसान धर्मजय सिंह के परिजनों ने सरकार आर्थिक मदद की गुहार लगाई है। चेन्नई के एक अस्पताल में भर्ती धर्मजय सिंह के इलाज पर अभी तक दो करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हो चुके हैं। परिवार की अर्थिक स्थित खराब होने पर परिजनों ने सरकार से अर्थिक मदद की गुहार लगाई है। ताकि आगे उनका इलाज हो सके। दरअसल, रीवा जिले के प्रगतिशील किसान कोरोना की चपेट में आने के बाद चार माह से जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। रीवा से परिजन मई माह में एयर एंबुलेंस से चेन्नई ले गए थे, जहां वे इकमो मशीन के सहारे सांस ले रहे हैं। परिजनों के मुताबिक इलाज पर अब तक दो करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। अभी इतना ही और खर्च डॉक्टर बता रहे हैं। धर्मजय सिंह की जिंदगी बचाने के लिए, परिजन हर प्रयास कर रहे हैं। किसान के बेटे नृपेंद्र सिंह ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया को पत्र लिखकर आर्थिक मदद की गुहार लगाई है। साथ ही मप्र के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से भी गुहार लगाई गई है। किसान के बेटे ने केंद्र और राज्य सरकार से मांग की है कि इलाज की राशि में 50 प्रतिशत छूट दिलाई जाए।

## पहले रीवा में चला इलाज

गौरतलब है कि रीवा जिले के ग्राम रकरी के धर्मजय सिंह (49) प्रगतिशील किसान हैं। खेती-किसानी के साथ ही वे सामाजिक कार्यों में हमेशा आगे रहते हैं। कोरोना काल में उन्होंने हर तरह लोगों की मदद की। लोगों की सेवा के दौरान ही उनकी तबीयत बिगड़ी और 30 अप्रैल को रीवा के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। कोरोना के लक्षण होने पर जांच कराई। दो मई को उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी।

## अभी दी जा रही कृत्रिम श्वांस

जांच में पता चला कि 95 प्रतिशत फेंफड़ा संक्रमित हो गया है। इसके चलते उन्हें 18 मई को एयर एंबुलेंस से इकमो मशीन की सहायता से चेन्नई के अपोलो (मेन) हास्पिटल में भर्ती कराया गया। जहां इकमो मशीन से उन्हें कृत्रिम श्वांस दी जा रही है।

## बेटे ने मदद के लिए लिखा पत्र

धर्मजय के पुत्र नृपेंद्र ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखकर बताया है कि चिकित्सकों ने फेंफड़े के प्रत्यारोपण का प्रस्ताव किया है। अब तक 2 करोड़ खर्च हो चुके हैं। परिवार की मदद से किसी तरह व्यवस्था बनाई गई, लेकिन अब रुपए नहीं हैं। अस्पताल प्रबंधन से इलाज की राशि में 50 प्रतिशत की छूट दिलाई जाए।

## सीएम शिवराज ने रीवा में किया था सम्मानित

गौरतलब है कि '**जागत गांव हमार**' ने 16 जनवरी 2021 के अपने अंक में प्रमुखता के साथ '**फल की खेती में फायदा**' शीर्षक से प्रमुखता के साथ खबर प्रकाशित की थी। इसमें बताया गया था कि प्रगतिशील किसान धर्मजय सिंह ने खेती-किसानी में विशिष्ट पहचान बनाई है। उन्होंने अपने खेतों में स्ट्राबेरी तैयार किया है। गुलाब की खेती भी व्यापक स्तर पर शुरू की है। इस पर किसान धर्मजय सिंह को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 26 जनवरी को रीवा के एसएएफ ग्राउंड में गणतंत्र दिवस समारोह में सम्मानित किया था।

**जागत गांव हमार के साथ मप्र के किसानों ने भी सरकार से मदद की उम्मीद की है।**

आर्थिक अनियमितताओं की एक भी जांच पूरी नहीं

# 26 बड़ी मंडियों में 5 साल में गड़बड़ी की 167 शिकायतें

संवाददाता, भोपाल

मप्र में काम कर रही कृषि मंडियों में गड़बड़ी की बीते 5 साल में 167 शिकायतें मिली हैं। लेकिन इनमें से किसी भी मामले की जांच अब तक पूरी नहीं हुई है। विभाग यही कह रहा है कि सभी 167 मामलों में जांच जारी है।

मतलब साफ है कि किसान और व्यापारियों से जुड़ी प्रदेश की बड़ी मंडियों में जो आर्थिक अनियमितता की शिकायतें आई हैं, उनके निपटारे में विभाग गंभीर नहीं है। विभाग की कछुआ चाल से हो रही जांच की प्रक्रिया सवालों के घेरे में है। प्रदेश की 258 बड़ी मंडियों में पद के दुरुपयोग और आर्थिक अनियमितताओं की साल 2016 से लेकर 2021 तक विभाग को 167 शिकायतें मिली हैं। गंभीर शिकायतों पर जांच भी शुरू हुई। लेकिन यह जांच सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह कर रह गई। क्योंकि ना किसी मामले में किसी अफसर पर कार्रवाई हुई, ना ही किसी जांच नतीजे पर पहुंची।

जितनी भी विभागीय जांच लंबित हैं, उनकी समीक्षा की जाएगी और जो भी दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। किसानों के साथ अन्याय नहीं होगा। ये किसानों की सरकार है।

**कमल पटेल**, कृषि मंत्री

## हर मंडी में गड़बड़ी

प्रदेश की मंडियों में दर्ज हुई शिकायतों के आंकड़ों पर नजर डालें तो भोपाल संभाग में 5 साल में 18, इंदौर में 39, उज्जैन में 6, ग्वालियर में 10, सागर में 7, जबलपुर संभाग में 83, रीवा संभाग में 4 शिकायतें दर्ज हुई हैं। हैरत की बात यही है कि सभी मामलों में सालों बीत जाने के बाद भी इनमें से किसी की जांच पूरी नहीं हुई है।

## भ्रष्ट अफसरों को शह

कृषि विभाग में गड़बड़ी की कछुआ चाल से हो रही जांच पर कांग्रेस हमलावर है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस विधायक के मुताबिक भाजपा सरकार में अफसरों की कार्यशैली को लेकर शिकायतें मिली थीं, जिसमें जांच के निर्देश दिए गए थे। लेकिन अब तक किसी अफसर के खिलाफ जांच पूरी ना हो पाना इस बात के संकेत हैं कि विभाग में भ्रष्ट अफसरों को संरक्षण हासिल है। किसानों के हित के लिए बनाई गई मंडियों में विभाग कितना गंभीर है इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 5 साल से ज्यादा बीतने के बाद भी गड़बड़ी करने वाले अफसर बेपरवाह हैं। जिन अफसरों के खिलाफ शिकायतें मिली है, उन पर कार्रवाई कब होगी यह यहां बड़ा सवाल है।

» बैगाचक क्षेत्र में प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के साथ बड़े स्तर पर ब्रॉडिंग की तैयारी

» निःशुल्क बीज उपलब्ध कराकर साढ़े चार सौ हेक्टेयर में कराई गई बोवनी

» अन्य दाल की तुलना में स्वादिष्ट होने के साथ पौष्टिक भी होती है बैगानी अरहर

# मध्यप्रदेश की बैगानी अरहर को मिलेगी राष्ट्रीय पहचान

संवाददाता, भोपाल/ डिंडोरी

संरक्षित जनजाति में शामिल बैगाओं द्वारा उत्पादित विलुप्त हो रही मध्यप्रदेश के डिंडोरी की बैगानी अरहर को राष्ट्रीय पहचान दिलाने की कवायद शुरू की गई है। कलेक्टर रत्नाकर झा द्वारा नई पहल करते हुए जिले में बैगानी राहर का उत्पादन बढ़ाने के साथ इसकी बड़े स्तर पर ब्रांडिंग कराने की भी कार्ययोजना तैयार कर ली है। आर्गेनिक और जीआई सर्टिफिकेशन कराने के बाद डिंडोरी के बैगाओं द्वारा उत्पादित बैगानी अरहर को राष्ट्रीय बाजार में उतारने की पहल होगी। बैगाचक क्षेत्र में प्रोसेसिंग यूनिट भी लगाई जा रही है। यहां बैगानी अरहर की पैकिंग कराकर बिक्री के लिए बाजार में उपलब्ध कराया जाएगा। गौरतलब है कि बैगा विलुप्त होती जनजाति में भी शामिल है। बैगानी अरहर के नाम से राष्ट्रीय बाजार में ब्रांडिंग होने के चलते बैगा जनजाति को भी एक अलग पहचान मिल सकेगी। जिला प्रशासन ने बैगानी अरहर (राहर) को एक जिला एक उत्पाद की श्रेणी में भी शामिल कर लिया है।

## पाला गिरने से पहले पक जाती है फसल

अमरकंटक और छत्तीसगढ़ के जंगलों से लगा क्षेत्र होने के चलते जिले भर में पाला भी पड़ता है। पाला के चलते दिसंबर जनवरी माह में अरहर की फसल सबसे अधिक प्रभावित होती है। बैगानी अरहर की खासियत यह है कि यह 80 से 90 दिन में ही पाला गिरने से पहले पककर तैयार हो जाती है, ऐसे में यह फसल पाले से प्रभावित नहीं होती। गौरतलब है कि बैगा जनजाति बैगानी अरहर की खेती बेबर तौर पर जंगलों में करते रहे हैं। बेबर खेती में जुताई नहीं होती, बीज यूं ही जंगल में बारिश के पहले फेंक दिए जाते हैं और अपने आप यह फसल तैयार हो जाती थी।

## क्या होती है बैगानी अरहर

बैगानी अरहर के दाने सफेद रंग के होते हैं। इसके बीज भी अन्य राहर की तुलना में बड़े होते हैं। इसके फूल लाल रंग के होते हैं, जबकि सामान्य राहर के फूल पीले होते हैं। यह फसल अन्य अरहर की तुलना में लगभग तीस दिन पहले ही पककर तैयार हो जाती है। बैगाओं के बारे में जानकार और बेबर स्वराज पुस्तक लिखने वाले नरेश विश्वास बताते हैं कि बैगानी अरहर में प्रोटीन की मात्रा 22.3 पाई जाती है, जबकि अन्य अरहर में यह मात्रा 22 प्रतिशत ही होती है। इसी के साथ ही इसमें फैट की मात्रा कम होती है। श्री विश्वास ने बताया बैगानी अरहर में मीठापन अधिक होने के चलते यह अन्य राहर की तुलना में अधिक स्वादिष्ट भी होती है।

बैगानी राहर दिखाते हीरालाल साहू।

## इनका कहना है

बैगानी अरहर विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गई थी। अब इसकी ब्रांडिंग कराकर बड़े स्तर पर बिक्री के लिए उपलब्ध कराने की कार्ययोजना है। बैगानी राहर उत्पाद की प्रोसेसिंग यूनिट बैगाचक क्षेत्र में ही लगाई जाएगी। तैयार उत्पाद का आर्गेनिक और जीआई सर्टिफिकेशन कराया जा रहा है। दाल की पैकिंग यहीं कराई जाएगी। इससे निश्चित ही बैगानी राहर को बड़ी पहचान मिल सकेगी। एक जिला एक उत्पाद में भी इसे शामिल किया गया है।

**रत्नाकर झा**, कलेक्टर डिंडोरी

बैगा जनजाति को मेड़ बंधान का लाभ देने के साथ निःशुल्क बीज देकर इसे बोवनी कराने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। बैगानी अरहर के बीज भी बैगाओं को निःशुल्क वितरित किए गए हैं। बोवनी के बाद फसल की लगातार मॉनीटरिंग की जा रही है। इस वर्ष 450 हेक्टेयर क्षेत्र में बैगानी राहर की बोवनी कराई गई है।

**अश्विनी झारिया**, उपसंचालक कृषि, डिंडोरी

### एपीडा व सीआईआई की संयुक्त कार्यशाला में बोलीं प्रियंका

# मध्यप्रदेश की कृषि उपजों की ब्रॉडिंग में जुटा मंडी बोर्ड

संवाददाता, भोपाल

हाल ही में आरसीवीपी नरोन्हा प्रशासन एकादमी, भोपाल में एपीडा (कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण) और सीआईआई (कान्फीडिरेशन ऑफ इंडियन इन्डस्ट्री) द्वारा आयोजित कृषि स्टार्टअप के लिए क्षमतावर्धन कार्यक्रम का आयोजन मप्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आयुक्त सह प्रबंध संचालक प्रियंका दास की मौजूदगी में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्जवलन कर किया गया। शुभारंभ अवसर पर एपीडा संस्था की डीजीएम समिधा गुप्ता, नई दिल्ली द्वारा एपीडा संस्था की कार्य प्रणाली की जानकारी दी। वहीं मप्र मंडी बोर्ड की प्रबंध संचालक प्रियंका दास ने मंडी बोर्ड और मंडी समितियों की कार्यप्रणाली की जानकारी देने के साथ-साथ मप्र में एपीडा के संचालन की नोडल एजेंसी होने के नाते एपीडा के माध्यम से मप्र के निर्यात को किस प्रकार बढ़ाने के संबंध में कार्य कर रहें हैं, के संबंध में जानकारी दी गई। उन्होंने मंडी बोर्ड द्वारा मध्यप्रदेश में उत्पादित हो रही कृषि उपजों की ब्राडिंग एवं मार्केटिंग, इन्फ्रास्ट्रक्चर डव्हलपमेंट, बिजीनेस रिफाम, कपिसिटी बिल्डिंग के साथ-साथ केंद्र सरकार की अतिमहत्वपूर्ण योजना एआईएफ के संबंध में बताया।

## हितग्राहियों को मिली राशि

प्रियंका दास ने बताया कि एआईएफ स्कीम एक कम दर पर ऋण उपलब्ध कराने की योजना है। जिसमें केंद्र सरकार द्वारा 1.00 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मप्र द्वारा उक्त योजना का व्यापक रूप से उपयोग कर 1008.25 करोड़ की योजनाएं सेंक्शन कराकर 526.92 करोड़ रुपए की राशि 1018 हितग्राहियों को उपलब्ध करा दिया गया है।

## खुद स्थापित कर सकते हैं उद्योग

प्रियंका ने बताया कि राज्य अपने क्षेत्र में विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए एआईएफ स्कीम के अंतर्गत ऋण प्राप्त कर सकते हैं। जिसमें विभिन्न प्रकार के वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज, असेइंग लेब, इलेक्ट्रानिक तौलकांटा, सार्टिंग ग्रेडिंग प्लांट, ड्राईंग यार्ड, ट्रेडिंग प्लेटफार्म, रायपेंनिंग चेंबर्स, प्रायमरी कलेक्शन सेंटर, इररेडिशन प्लांट्स, प्रायमरी प्रोसेसिंग सेंटर, दाल चावल आटा तेल मिलों के साथ-साथ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट स्कीम उक्त योजना के अंतर्गत स्थापित की जा सकती है।

## जिंसों को किया जा रहा तैयार

मध्यप्रदेश में मल्टी क्रॉप एग्री एक्सपोर्ट क्लस्टर बनाकर जिलों में विभिन्न जिंसों को निर्यात के लिए तैयार किया जा रहा है। जिसमें उज्जैन जिले में लहसुन और आलू, खरगोन में अनार और अमरूद, शाजापुर में प्याज, संतरा, अनार और आलू, इंदौर में प्याज और आलू, रतलाम जिले में लहसुन और हरा मटर, छिंदवाड़ा में हरा मटर, हरी मिर्च, संतरा और टमाटर को निर्यात के लिए चिन्हित किया गया है।

## जिलों का किया चयन

उन्होंने बताया कि सिंगल क्रॉप एग्री एक्सपोर्ट क्लस्टर में आगर मालवा, धार, नीमच, सीहोर, शिवपुरी, खंडवा, झाबुआ, सागर, देवास, जबलपुर और रीवा को विभिन्न उपजों के निर्यात के लिए चयनित किया गया है। एआईएफ योजना में कोई भी व्यक्ति फर्म, संस्था एफपीओ, एफपीसी आदि उक्त योजना का लाभ प्राप्त कर सकती है।

## यह रहे मौजूद

कार्यक्रम में एपीडा की डीजीएम समिधा गुप्ता, सीआईआई के चेयरमेन निखिल कौशिक, एपीडा के एजीएम प्रशांत बाघमारे, एमएसएमई के नीलेश त्रिवेदी, डीजीएफटी इंदौर के चंद्रकांत राम, ईसीजीसी के विकास धौलपुरे, विभिन्न एफपीओ और एफपीसी के प्रतिनिधि मौजूद थे।

# फसल उत्पादन का किसानों को दिया प्रशिक्षण

### कृषि वैज्ञानिकों ने अत्मनिर्भरता के दिए सुझाव

**सागर।** नेशनल फर्टिलाईजर्स लिमिटेड (भारत सरकार का उपकम ) के क्षेत्रीय कार्यालय सतना द्वारा कृषि विज्ञान केंद्र सागर में आजादी का अमृत महोत्सव आत्म निर्भर भारत के अंतर्गत संतुलित उर्वरक उपयोग पर एक दिवसीय किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मास्क वितरण के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ख्याल रखा गया। कार्यक्रम का प्रारंभ राष्ट्रगान के साथ किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डॉ. केएस यादव प्रधान कृषि वैज्ञानिक एवं प्रभारी कृषि विज्ञान केंद्र सागर के द्वारा पर्यावरण के अनुरूप फसल उत्पादन और नई प्रजातियों के बारे में बताया। डॉ. ममता सिंह कृषि वैज्ञानिक पादप प्रजनन द्वारा फसलों में आवश्यक मृदा पोषक तत्वो के बारे में और संतुलित उर्वरक उपयोग पर विस्तार से समझाया। डॉ. आशीष त्रिपाठी वैज्ञानिक पादप रोग, विज्ञान द्वारा उपस्थित सभी किसानों को पौधों में लगने वाले रोग उनके लक्षण, उनसे होने वाली हानि और उनकी रोकथाम के बारे में जानकारी दी गई। कार्यक्रम में सतना से आए अविनाश कुमार सरोंजा प्रभारी क्षेत्रीय कार्यालय सतना द्वारा किसानों को कंपनी के विभिन्न उत्पादों की जानकारी दी गई और कृषकों को मृदा परिक्षण कराने के लिए जागरुक किया। कार्यक्रम के अंत में मुकेश कुशवाहा जिला प्रभारी सागर द्वारा संबोधित करते हुए प्रश्नोत्तरी आयोजित करवाई गई। कार्यक्रम में शामिल सभी 58 किसानों ने उक्त आयोजन की सराहना भी की।

# मुर्गी पालन से बुंदेलखंड होगा कुपोषण मुक्त

### वैज्ञानिकों ने प्रशिक्षण किसानों को सिखाए हुनर

**टीकमगढ़।** कृषि विज्ञान केंद्र, टीकमगढ़ द्वारा सृजन एनजीओ के साथ डॉ. एसके खरे और डॉ. बीएस किरार द्वारा ग्राम बिलगाय, जतारा-टीकमगढ़ में मुर्गीपालन पर सात दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण में 20 अनुसूचित जाति के छोटे एवं भूमिहीन किसानों ने भाग लिया, जिसमें किसानों को मुर्गियों को बाड़े में पालने वाली नस्लों की पहचान, लक्षण, चूजों की देखरेख और प्रबंधन उनके खानपान व रहने की व्यवस्था से लेकर रोग प्रबंधन और टीकाकरण की तकनिकी जानकारी के साथ-साथ चूजों को कहां से प्राप्त करें उन संस्थानों की जानकारी एवं बाजार से रूबरू कराया गया। प्रशिक्षण का उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाने के साथ स्वरोजगार एवं स्वाबलंबन है, जो कि आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ता कदम है। केंद्र के प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉ. बीएस किरार ने कृषकों को मुर्गीपालन की आर्थिकी के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए समझाया कि मुर्गीपालन ग्रामीण परवेश में कम लागत मे अधिक आय का एक अच्छा विकल्प है। डॉ.एसके सिंह ने बताया कि बाड़े में मुर्गी पालन करने के साथ ही सब्जियां लगाकर अपनी आय को को कैसे दोगुना करें। सब्जियों की किस्म के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि सब्जी के साथ-साथ अंडा एवं मांस का उपयोग कर बुंदेलखंड में कुपोषण को दूर किया जा सकता है। प्रशिक्षण आयोजन के सचिव डॉ. एसके खरे और सहसचिव डॉ. आईडी सिंह थे। सृजन एनजीओ से चंचल त्रिवेदी ने सहभागिता की एवं सहयोग प्रदान किया।

# भोपाल की 15 पंचायतों में 100 फीसदी वैक्सीनेशन

संवाददाता, भोपाल

भोपाल की 15 ग्राम पंचायतें 100 फीसदी वैक्सीनेशन की लिस्ट में शामिल हो गई हैं। यहां 18+ वाले सभी लोगों को वैक्सीन का फर्स्ट डोज लगाया जा चुका है, लेकिन चुनौती उन 90 प्रतिशत गांवों में हैं, जहां वैक्सीन लगवाने से कुछ लोग ही बचे हैं। कर्फ्यू खुलने के बाद कोई नौकरी की तलाश में किसी शहर-प्रदेश में चले गए या फिर गांव में लंबे समय से मौजूद नहीं है। इन्हें जिला प्रशासन कॉल करके बुलावा भेज रहा है। जिले में 187 ग्राम पंचायतें हैं। इनमें से 15 पंचायतें 100 प्रतिशत वैक्सीनेशन का टॉरगेट पूरा कर पाई है। इसके अलावा बैरसिया नगर परिषद में सभी 25 हजार 118 लोगों को वैक्सीन का पहला डोज लग चुका है। जिससे यह भी

100 प्रतिशत वैक्सीनेशन करने वाले निकायों में शामिल हो गई हैं। अब अफसरों का फोकस 172 ग्राम पंचायतों पर है।

## वोटर लिस्ट से वैक्सीनेशन

दरअसल, कोई भी कहीं भी वैक्सीन लगवा सकता है। शुरुआत में कई शहरी लोगों ने गांवों के सेंटरों में पहुंचकर वैक्सीन लगवा ली। ताकि शहरी केंद्रों पर भीड़ और वैक्सीन की कमी से बच सके। इस कारण जिला पंचायत ने वोटर लिस्ट के हिसाब से ग्रामीणों को वैक्सीन लगाना शुरू की। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की मदद से लोगों को पीले चावल देकर सेंटरों पर बुलाया गया।

## इनका कहना है

वोटर लिस्ट के हिसाब से वैक्सीन लगा रहे हैं। इससे 15 पंचायतें 100 प्रतिशत वैक्सीनेशन के दायरे में आ गई है। अधिकांश पंचायतें भी इस कैटेगिरी में आ रही है। जो लोग वैक्सीन लगवाने से छूटे हैं और बाहर है उन्हें कॉल करके बुला रहे हैं। यदि उन्होंने बाहर वैक्सीन लगवा ली है तो उनसे सर्टिफिकेट मंगवा रहे हैं। ताकि पारदर्शिता बनी रहे। सचिवों को रोज कॉल करके बुलावा भेजने को कहा है।

**विकास मिश्रा**, सीईओ, जिला पंचायत भोपाल

**» मंत्री हरदीप सिंह डंग ने कहा- मध्यप्रदेश में गाय पालने को लेकर बनाया जाए कानून**

**» गौपालन के लिए कर्मचारियों से पांच सौ रुपए प्रति माह टैक्स के रूप में लिए जाएं**

**» गाय नहीं पालने वाले उम्मीदवार का पर्चा चुनाव आयोग को निरस्त कर देना चाहिए**

# गाय पर सियासत

संवाददाता, भोपाल

प्रदेश सरकार में मंत्री हरदीप सिंह डंग के एक बयान को लेकर को सियासत गरमा गई। दरअसल, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री डंग ने मीडिया से चर्चा में कहा था कि प्रदेश में गाय पालने को लेकर कानून बनाया जाए। जिन कर्मचारियों की सैलरी 25 हजार रुपए से ज्यादा है, उनसे हर महीने 500 रुपए लिए जाएं। साथ ही खेती किसानी से जुड़े क्रय-विक्रय करने वाले किसानों के लिए गाय पालना अनिवार्य किया जाए। जो जनप्रतिनिधि चुनाव लड़ना

चाहता है, उसके लिए गाय पालना अनिवार्य हो। गाय नहीं पालने वाले व्यक्ति का चुनाव आयोग फार्म निरस्त करे। मैं इस बारे में चुनाव आयोग को भी पत्र लिखूंगा। इसके बाद कांग्रेस का बयान सामने आया। भोपाल विधायक आरिफ मसूद ने कहा- हमें डंग का प्रस्ताव मंजूर है, लेकिन भाजपा सरकार ये वादा करे कि हमारे गाय पालने पर मॉब लिंचिंग नहीं होगी। वहीं, पूर्व मंत्री व विधायक पीसी शर्मा ने कहा कि कमलनाथ सरकार ने राज्य में एक हजार गौशालाएं बनाने की घोषणा की थी, अगर यह गौशाला बन जाती तो गायें सड़कों पर घूमते नहीं देखी जाती। मध्य प्रदेश भाजपा कार्यालय में मीडिया से चर्चा में डंग ने कहा कि गोमाता की रक्षा करने का धर्म हम सभी का है। यह सिर्फ नारे तक सीमित नहीं रहना चाहिए। हालांकि, उन्होंने इसे अपनी व्यक्तिगत राय बताया और कहा कि पार्टी सहित अन्य मंचों पर इस बात को रखूंगा।

## कांग्रेस ने उठाया सवाल

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा ने कहा कि उन्होंने लोगों से गोपालन को लेकर अपील की है। इसमें कोई बुराई नहीं है। प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री और प्रवक्ता रवि सक्सेना ने मंत्री के सुझाव पर कहा कि उन्हें यह जवाब देना चाहिए कि गोशालाएं दुर्दशा की शिकार क्यों हैं।

## सीएम ने लिया था निर्णय

**इधर,** समय पर विद्युतीकरण नहीं होने पर पशुपालन विभाग में सौर ऊर्जा के स्थान पर विद्युत विभाग को काम देने का प्रस्ताव प्रशासन को दिया था। सीएस द्वारा निर्णय लिया गया कि 550 गौशालाओं में सौर ऊर्जा से विद्युत उपकरण के स्थान पर 430 गौशालाओं में पारंपरिक ऊर्जा से रोशन कराएं। इसके लिए राशि भी ऊर्जा विभाग को हस्तांतरित की जाए जिससे समय पर काम पूरा हो सके।

## बिजली पहुंचाने इस तरह की दिक्कतें

रीवा जिले की शती सेंगर ग्राम पंचायत में तकटिवं तेरह सौ एकड़ में गौशाला का निर्माण कराया गया है। गौशाला से बिजली का खंबा एक हजार मीटर की दूरी पर है। इसके लिए तार बिछाने के लिए खर्च साढ़े चार लाख रुपए आएगा। इसी तरह देवास जिले के बरदू ग्राम में गौशाला से ट्रांसफार्मर की दूरी बारह सौ मीटर है। यहां पर करीब पौने पांच लाख का खर्च आएगा। बड़े खर्च को बचाने के लिए सौर ऊर्जा से बिजली पहुंचाने का निर्णय लिया गया था। यही वजह है कि पशुपालन विभाग ने आरकेवीवाई योजना से विद्युतीकरण का काम नवीन एवं नवकरणीय विभाग को दिया था लेकिन यह विभाग एक साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी काम पूरा नहीं कर पाया है।

## कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा, गाय पालना समय की जरूरत

कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा गाय भारत की जीवनदायिनी

है और गौ वंश पालने से जैविक खेती को बढ़ावा मिलेगा। यह वर्तमान की जरूरत है कि गाय हर घर में पाली जाए जिससे खेती में भी कम लागत लगे। किसानों अधिक से अधिक दूध उत्पादन करेंगे तो उनकी आय भी बढ़ेगी। यही नहीं, किसान गाय पालन से सीएनजी का भी उत्पादन शुरू कर सकते हैं। इसके लिए सरकार उन्हें विभिन्न तरह से प्रोत्साहन भी सब्सिडी के रूप में देती है।

## वीडी शर्मा बोले, चार गाय पालें

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने मंत्री हरदीप सिंह डंग की

मांग का समर्थन करते हुए कहा दो नहीं चार गाय लोग पालें। हर व्यक्ति को गौ पालन करना चाहिए। गौ पालन से व्यक्ति और देश दोनों स्वस्थ रहेंगे। अभी ये कानून नहीं बना है। गाय हमारी माता हैं। उनका संरक्षण करना हमारी जिम्मेदारी है। रही कांग्रेस नेताओं की बात तो उनकी आदता हो गई है बीच में टांग अड़ाने की। उनकी करनी और कथनी जनता देख चुकी है।

## गौशालाओं में नहीं पहुंची रोशनी

**इधर,** प्रदेश में सैकड़ों गौशालाओं की स्थिति आज भी ऐसी है कि कहीं बिजली नहीं है तो कई अन्य सुविधाओं के अभाव में यह चल रहीं हैं। हालांकि विद्युतीकरण के लिए पशुपालन विभाग द्वारा आरकेवीवाई योजना के तहत बिजली का काम नवीन एवं नवीकरणीय विभाग को दिया गया था, लेकिन एक साल की लंबी अवधि गुजर जाने के बाद भी विभाग इस काम को पूरा नहीं करा पाया है। वहीं हाल ही में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक में निर्णय लिया गया है कि अब नवकरणीय की जगह ऊर्जा विभाग यह काम करेगा।

## हर पंचायत में एक गौशाला

सरकार ने हर ग्राम पंचायत में एक गौशाला बनाने का निर्णय लिया था। इस योजना के तहत प्रथम चरण में एक हजार चार ग्राम पंचायतों में गौशाला बनाने के लिए मंजूरी मिली। मनरेगा के अंतर्गत पूर्ण कराई गई इन गौशालाओं में बिजली नहीं होने की समस्या बरकरार है। वहीं पानी के लिए प्रत्येक गौशाला को 1.66 लाख की राशि दी गई है। अब कहा जा रहा है कि गौशालाओं के संचालन का काम स्व सहायता समूह व अन्य संस्थाओं को सौंपा जा रहा है। इसके लिए बाकायदा पंचायतों के माध्यम से अनुबंध किए गए हैं।

## पंचायतों में असमंजस की स्थिति

बहरहाल अब भी ग्राम पंचायतों में गौशालाओं के निर्माण को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। दरअसल पंचायत दर्पण पोर्टल में जहां 690 गौशालाएं दर्ज हैं, वहीं मनरेगा के रिकॉर्ड में 1152 गौशालाएं हैं। पशुपालन विभाग में 1004 गौशालाएं स्वीकृत हैं, जबकि 973 गौशालाओं का ही निर्माण कार्य ही पूरा हुआ है।

### किसानों को प्रोत्साहन करने शुरू की गई आत्मा परियोजना

## पुरस्कारों के लिए किसानों से 30 तक बुलाए आवेदन

**भोपाल।** आत्मा परियोजना के तहत संचालित कृषि विस्तार सुधार कार्यक्रम में 2020-21 के लिए कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, मत्स्य व अभियांत्रिकी गतिविधियों से संबंधित किसानों और कृषक समूहों से 30 अगस्त तक आवेदन बुलाए गए हैं। यह योजना किसानों को उनके नवाचार और उन्नात खेती के लिए प्रोत्साहन के लिए शुरू की गई है। परियोजना संचालक ने बताया कि जिला स्तरीय सर्वोत्तम कृषक पुरस्कार अलग-अलग गतिविधि में दस किसानों को दिए जाएंगे। पुरस्कार की राशि 25-25 हजार होगी। इसी तरह विकासखंड स्तरीय पांच किसानों को 10-10 हजार रुपए और पांच समूहों को 20-20 हजार रुपए के पुरस्कार दिए जाएंगे। मूल्यांकन समिति द्वारा ऐसे किसानों का चयन किया जाएगा जिन्होंने उन्नात तकनीक अपनाकर कृषि में बदलाव किया हो और इससे उपज और उत्पादकता बढ़ी हो। या किसान ने कोई उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की हो।

## प्रकृति को बनाएं हरा-भरा

**भोपाल।** मप्र के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक वर्ष तक प्रतिदिन पौधा लगाने का संकल्प लिया है। उनका यह निर्णय अभिनंदनीय है। मुख्यमंत्री का पौधा लगाने का यह संकल्प हमें पर्यावरण संरक्षण और उसे हरा भरा बनाए रखने की प्रेरणा देता है। आप भी पौधा लगाएं और प्रकृति को हरा भरा बनाए रखने में अपना योगदान दें। यह कहना है कि प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल का। दरअसल, अभी हाल ही में भोपाल के स्मार्ट पार्क में सीएम शिवराज के साथ कृषि मंत्री कमल पटेल ने भी मधुकामिनी का पौधा रोपा। मधुकामिनी का पौधा और इसका पुष्प न केवल देखने में अत्यंत सुंदर होता है, अपितु यह स्वांस रोग संबंधी बीमारियों में प्रभावी माना जाता है।

# प्रदेश की ग्रामीण विकास योजनाओं से बदल रहा परिवेश

ऋषभ जैन,
अधिकारी
जनसंपर्क, मप्र

**प्रदेश को कई योजनाओं में देश में प्रथम स्थान मिलने से इसकी पुष्टि होती है। ग्राम सभाओं में भागीदारी, पंचायतों के सशक्तीकरण, सामूहिक विकास में समुदाय का समावेशन, सामुदायिक निगरानी, सहभागिता, सामुदायिक स्वामित्व जैसे मुद्दों के साथ ग्रामीण अधोसंरचना विकास, मूलभूत सुविधाएं, आवागमन, सामाजिक-आर्थिक सशक्तीकरण, आत्म-निर्भरता, रोजगार-स्व-रोजगार, नवीन तकनीकियों की ग्राम स्तर तक पहुंच, विशेषकर शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और आजीविका क्षेत्र में प्रतिबद्धता से काम किए जा रहे हैं।**

प्रदेश में गांवों की स्थिति अब तेजी से सुधर रही है। ग्रामीण इलाकों में विकास के नए सोपान गढ़े जा रहे हैं। प्रदेश को कई योजनाओं में देश में प्रथम स्थान मिलने से इसकी पुष्टि होती है। ग्राम सभाओं में भागीदारी, पंचायतों के सशक्तीकरण, सामूहिक विकास में समुदाय का समावेशन, सामुदायिक निगरानी, सहभागिता, सामुदायिक स्वामित्व जैसे मुद्दों के साथ ग्रामीण अधोसंरचना विकास, मूलभूत सुविधाएं, आवागमन, सामाजिक-आर्थिक सशक्तीकरण, आत्म-निर्भरता, रोजगार-स्व-रोजगार, नवीन तकनीकियों की ग्राम स्तर तक पहुंच, विशेषकर शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और आजीविका क्षेत्र में प्रतिबद्धता से काम किए जा रहे हैं। इन तमाम प्रयासों से गांवों की तस्वीर बदलती दिख रही है। ग्रामीण क्षेत्र में उन्नत कृषि, पशुपालन में बुनियादी सुविधाएं, सिंचाई, भंडारण, वृहद बाजारों को गांव से जोड़ने के लिए भी उल्लेखनीय जतन किए गए हैं। वैज्ञानिक ढंग से विकास की प्रक्रिया का अनुसरण किए जाने से परंपरागत आय के संसाधनों पर निर्भरता कम होने के फलस्वरूप सकारात्मक परिवर्तन आना शुरू हुए हैं। सूक्ष्म उद्यमशीलता को बढ़ावा, फलदार पौधरोपण, व्यावसायिक सब्जी एवं दुग्ध उत्पादन में बढ़त होने से कृषकों की आय में बढ़ोतरी हो रही है। इससे गांवों की समृद्धि के द्वार खुलते जा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र में हो रहे सामाजिक व्यवहार परिवर्तन, विकास के प्रति सामाजिक लामबंदी, विभाग की प्रतिबद्धता, ग्रामीणों में विकास की ललक एवं जज्बे को देखकर कहा जा सकता है कि ग्रामीण परिवेश तेजी से बदल रहा है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में पिछले वित्त वर्ष में तकरीबन 34 करोड़ मानव दिवस का सृजन हुआ। यह उपलब्धि अब तक की सर्वाधिक है। यह प्रदेश विगत वर्ष लगभग एक करोड़ 6 लाख मजदूरों को रोजगार देकर देश में अग्रणी रहा है। इस वित्त वर्ष में 12 लाख 94 हजार कार्य शुरू किए गए हैं। इनमें मुख्य रूप से पौधा-रोपण, स्कूल डायनिंग टेबल, कैच द रैन जैसे कार्य शामिल हैं। प्रथम तिमाही में मानव दिवसों का बजट 10 करोड़ 50 लाख निर्धारित था। इनमें अभी तक 65 लाख 58 हजार मजदूरों को रोजगार देकर 14 करोड़ 80 लाख मानव दिवस सृजित किए गए। 37 लाख 56 हजार जॉब कार्डधारी परिवारों के 66 लाख 21 हजार श्रमिकों ने लगभग 15 करोड़ मानव दिवस सृजित किए हैं। मानव दिवस सृजन में प्रदेश देश में तीसरे स्थान पर है। अनुसूचित जन-जाति के परिवारों को रोजगार देने के मामले में प्रदेश देश में पहले स्थान पर है। लगभग 12 लाख 71 हजार आदिवासी परिवारों द्वारा करीब 4 करोड़ 86 लाख मानव दिवस सृजित किए जाकर लगभग 2 हजार 790 करोड़ रुपए की मजदूरी का भुगतान किया जा चुका है। इस वर्ष में अब तक एक लाख 23 हजार कार्य पूरे किए जाने के बाद 12 लाख के करीब कार्य प्रगति पर हैं। कोरोना की पहली लहर में पिछले वित्त वर्ष में एक करोड़ 6 लाख मजदूरों को रोजगार देकर यह प्रदेश देश में अग्रणी स्थान पर है। कोरोना की दूसरी लहर के चलते ग्राम स्तर पर कंटेनमेन्ट जोन निर्मित किए गए। इन जोन के बाहर के मजदूरों को रोजगार दिलाया गया, जिससे श्रमिकों को रोजगार मिल सका। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में पूर्व से गठित स्व-सहायता समूहों द्वारा ग्रामीण निर्धन परिवारों को संगठित कर उनके आर्थिक, सामाजिक सशक्तीकरण के काम किये जा रहे हैं। समूह सदस्यों को समूहों, ग्राम संगठनों, संकुल स्तरीय संघों के माध्यम से बैंक ऋण के रूप में सस्ती ब्याज दरों पर आसान प्रक्रिया से वित्तीय सहायता दी जा रही है। इससे उन्हें बिना कठिनाई के सुदृढ़ करने के अवसर मिलने लगे हैं। मिशन के अंतर्गत सभी जिलों में 44 हजार 800 ग्रामों में यह गतिविधियां संचालित हैं। ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे तकरीबन 37 लाख 73 हजार जरूरतमंद निर्धन परिवारों को 3 लाख 31 हजार स्व-सहायता समूहों से जोड़ा गया है। साथ ही 31 हजार ग्राम संगठन और एक हजार संकुल स्तरीय संगठन गठित हैं। कृषि एवं पशुपालन आधारित आजीविका गतिविधियों से लगभग 12 लाख 54 हजार परिवारों को जोड़ा गया है। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में अधिकांश परिवारों की आजीविका कृषि पर आधारित है इसलिये कम लागत में अधिक उपज के लिए उन्नत कृषि पद्धति अपनाने, नवीन तकनीकी का प्रयोग, उन्नत बीज प्रयोग, जैविक खाद, जैविक कीटनाशक के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रदेश में लगभग 6 हजार सामुदायिक स्त्रोत व्यक्ति (सीआरपी) के रूप में कृषि सखीं चिन्हित की गई हैं। इनमें से कुछ सीआरपी ने उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और छत्तीसगढ़ में समूह सदस्यों को मार्गदर्शन देकर मानदेय के रूप में अतिरिक्त आय अर्जित कराई है। मध्यप्रदेश की कृषि सखियों की मांग इन राज्यों में लगातार बनी हुई है।प्रदेश में स्वच्छ भारत मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 62 लाख 92 हजार शौचालय बनाए जाकर प्रदेश के सभी ग्रामों को खुले में शौच की स्थिति से मुक्त करने का लक्ष्य 2 अक्टूबर 2018 को ही प्राप्त कर लिया गया था। मिशन का दूसरा चरण एक अप्रैल 2020 से प्रारंभ किया जाकर आगामी पाँच वर्ष में सभी ग्रामों में ओडीएफ स्थिति की निरंतरता के लिए सामुदायिक स्वच्छता परिसर, ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के कार्य तथा यदि कोई पात्रताधारी घर शौचालय विहीन है तो उसमें शौचालय निर्माण कराया जाकर ग्रामों को ओडीएफ प्लस बनाया जाएगा। इस वर्ष 22 हजार 63 ग्रामों में ठोस कचरा एवं ग्रे-वाटर प्रबंधन के कार्य किए जाएंगे। दूसरे चरण में 131 करोड़ की लागत से एक लाख 9 हजार से ज्यादा हितग्राहियों के लिए व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण पूर्ण किया गया है। धार्मिक स्थल, पर्यटक स्थल एवं अधिक आवाजाही वाले ग्रामों में अब तक पौने 9 हजार सामुदायिक स्वच्छता परिसरों का निर्माण भी किया जा चुका है। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित विभिन्न योजनाओं और विकास कार्यों के क्रियान्वयन से गाँवों की तस्वीर बदलती नजर आ रही है।

**ग्रामीण महिलाएं नवाचार से हो रहीं आत्म-निर्भर:** स्व-सहायता समूहों से जुड़ी महिलाएं अब रसोई घर के डब्बों की जगह बचत का पैसा बैंक खाते में जमा करती हैं। लगभग साढ़े 9 लाख समूह सदस्य महिलाओं के अलग बचत खाते खुले हुए हैं। सवा 28 लाख से ज्यादा समूह सदस्यों ने बीमा भी करवाया है। महिलाओं ने कई नवाचार करते हुए ऐसे काम भी करना शुरू कर दिए हैं। श्योपुर जिले के कराहल ब्लॉक के ग्राम डूंडीखेडा की सुनीता आदिवासी आजीविका एक्सप्रेस सवारी वाहन का संचालन करती हैं। श्योपुर में स्व-सहायता समूह ने हाल ही में ऑक्सीजन प्लांट का संचालन भी शुरू किया है। समूहों द्वारा आत्मनिर्भर गौ-शालाओं का संचालन, फ्लाई एश से ब्रिक्स निर्माण, वनोपज संग्रहण एवं भंडारण, सड़क संधारण, नल-जल योजनाओं का संचालन, विद्युत बिल वितरण एवं संग्रहण, ग्राम सभाओं में भागीदारी कर सामुदायिक विकास के मुद्दों पर चर्चा, निर्णय और निगरानी में भी सक्रिय भूमिका निभाने के ऐसे कार्य हैं, जिनको देखकर आश्चर्य किया जा सकता है। एक समय वह था, जब महिलाएं घरों की चहारदीवारी में चूल्हे-चौके के सीमित दायरे में जीवन गुजारा करती थीं, पर अब ग्रामीण महिलाएं किसी पर बोझ नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर, सशक्त नेतृत्व की पहचान बनती जा रही हैं। इनके पास आजीविका के बेहतर अवसर हैं। इसीलिये वे आत्मनिर्भर के साथ सम्मानित भी हैं।

## गुजर गया वह छोटा ग्रह

वह छोटा ग्रह पृथ्वी के पास से गुजर गया, जिसे खतरनाक माना जा रहा था। वैसे तो वैज्ञानिकों को यह पता था कि यह मध्य आकार का छोटा ग्रह 21 अगस्त को पृथ्वी के कुछ करीब से गुजरेगा, लेकिन अफवाहों के कारण आशंकाओं का बाजार खड़ा करने वाले भी कम नहीं थे। कुछ का कहना था कि यह छोटा ग्रह सुबह के समय टकराएगा, तो कुछ ने कहा देर रात, लेकिन जब यह करीब से गुजरा, तो भारत में घड़ी रात के करीब आठ बजकर 40 मिनट बजा रही थी। अफवाह का बाजार गर्म करने वाले इसके गुजर जाने पर ज्यादातर चुप लगा गए, क्योंकि यह खगोलीय घटना गंभीर तो थी, लेकिन इससे ज्यादा खतरे की गुंजाइश नहीं थी। यह 2016 एजे193 नाम का ग्रह पृथ्वी के करीब 34 लाख 27 हजार 445 किलोमीटर पास से गुजरा है और 94 हजार किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार बढ़ा जा रहा है। 1.4 किलोमीटर व्यास के आकार वाले इस छोटे ग्रह को खगोलविद 24 अगस्त तक ज्यादा टकटकी लगाए देखेंगे। पृथ्वी के करीब से गुजरने के लिहाज से नासा ने इसे अगर संभावित खतरा घोषित किया था, तो यह एक तरह से खगोलविदों केशोध-अध्ययन की कमी ही थी।

धरती की ओर बढ़ती और धरती के पास से गुजरती हर चीज खतरनाक नहीं होती, लेकिन इंसानों के मन में जो भय है, उसका कोई इलाज नहीं। चूंकि हमने पृथ्वी और वायुमंडल के साथ ज्यादातर खिलवाड़ ही किया है, इसलिए हममें से ज्यादातर लोगों को भय सताता है कि पृथ्वी या सृष्टि हमसे बदला लेगी। खत्म हो जाने का भय सबसे बड़ा है और जिसका कोई पुख्ता उपाय विज्ञान के पास भी नहीं है। नासा को बहुत सोच-समझकर ही ऐसी आशंकाओं का इजहार करना चाहिए। मामूली आशंकाओं के आधार पर चेतावनी जारी करके सबको चिंता में डालने की नौबत नहीं आनी चाहिए। नासा ने इसे अपोलो श्रेणी के ऐसे छोटे ग्रह के रूप में वर्गीकृत कर रखा है, जिसके पृथ्वी की कक्षा से टकराने की आशंका है। कक्षा से टकराने या कक्षा से गुजरने का कतई यह मतलब नहीं कि यह छोटा ग्रह पृथ्वी से टकराने वाला था। यह तो पृथ्वी की कक्षा के उस क्षेत्र से गुजरा है, जहां मानव निर्मित कोई उपग्रह या सैटेलाइट तक मौजूद नहीं है।

हमें पृथ्वी की रक्षा के बारे में सोचना जरूर चाहिए, लेकिन डरना कोई उपाय नहीं है। खगोलीय रूप से किसी भी बड़े या छोटे ग्रह के परस्पर टकराने का आशंका नहीं बराबर है। अब तक कुल 1,18,846 छोटे ग्रह पहचाने गए हैं, जिनमें से 14,570 अपोलो श्रेणी में आते हैं। ज्यादातर ऐसे छोटे ग्रह लगातार परिक्रमा में लगे हैं। इस गुजरे ग्रह की ही बात करें, तो यह अब 65 साल बाद 19 अगस्त 2080 को पृथ्वी के करीब से गुजरेगा, लेकिन इस बार की तरह वह ज्यादा करीब नहीं आएगा। ऐसे छोटे ग्रह आमतौर पर पृथ्वी की कक्षा या उसके करीब से गुजरते हैं, लेकिन इसे इसलिए महत्व मिल गया, क्योंकि यह पृथ्वी की कक्षा के करीब मौजूद 99 फीसदी छोटे ग्रहों से अपेक्षाकृत बड़ा है। गौर करने की बात है कि वैज्ञानिक इसे साल 2016 से ही पृथ्वी के करीब आता देख रहे थे, अब आने वाले कुछ वर्षों तक जाते हुए देखेंगे। यह फिर सूर्य के करीब पहुंचेगा और फिर पृथ्वी की ओर लौटेगा। लेकिन तब तक हमें कोशिश करनी चाहिए कि दुनिया आज से बेहतर हो और इंसानों में बढ़ता अपराधबोध जनित भय भी कम हो।

# कृषि क्षेत्र में अपरिमित संभावनाओं से भरपूर स्वर्णिम मध्यप्रदेश

क्रांतिदीप अलूने,
उप संचालक, मप्र
जन संपर्क

**कोरोना काल की अप्रत्याशित और अभूतपूर्व चुनौतियों के बीच मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार ने लोक-कल्याणकारी कार्यों से मिसाल कायम की है। इसका उदाहरण कृषि क्षेत्र में मिल रही ऐतिहासिक उपलब्धियां और सफलताएं हैं, जिनकी सराहना प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी की है।**

कृषि क्षेत्र में अपरिमित संभावनाओं के द्वार खोलकर कैसे किसानों को अग्रणी और आत्म-निर्भर बनाया जा सकता है, इसका मध्यप्रदेश स्वर्णिम आदर्श प्रस्तुत कर रहा है। दरअसल, कोरोना काल की अप्रत्याशित और अभूतपूर्व चुनौतियों के बीच मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार ने लोक-कल्याणकारी कार्यों से मिसाल कायम की है। इसका उदाहरण कृषि क्षेत्र में मिल रही ऐतिहासिक उपलब्धियां और सफलताएं हैं, जिनकी सराहना प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी की है। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान स्वयं किसान हैं और वे किसानों के हितों के लिए प्रतिबद्धता से कार्य करने के लिए जाने जाते है। उनके डेढ़ दशक से ज्यादा के कार्यकाल में कृषि के क्षेत्र में नवाचार और आधुनिकीकरण पर ध्यान दिया गया है। इसके दीर्घकालीन प्रभाव ही है कि कृषि कर्मण अवार्ड को लगातार जीतकर प्रदेश ने इतिहास रचा है। प्रदेश में अनाज, सब्जी और फलों की उत्पादन लागत में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। पशुपालन, मछली पालन और मधुमक्खी पालन को भी लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। राज्य की विविधतापूर्ण जलवायु को दृष्टिगत रखते हुए सरकार बेहतर तालमेल स्थापित कर सभी क्षेत्रों में रहने वाले किसानों को प्रशिक्षण के साथ समुचित सहायता भी देती रही है। सोयाबीन और गेहूं के उत्पादन में मप्र ने नित नये कीर्तिमान स्थापित किए हैं। सोयाबीन खरीफ मौसम में प्रदेश में सर्वाधिक बोई जाने वाली फसल है। इसके साथ धान, मक्का, अरहर, मूंग, उड़द, ज्वार, बाजरा, कोदो, कुटकी, तिल और कपास का भरपूर उत्पादन होने लगा है। रबी की फसलों में गेहूं, चना, मटर, मसूर, सरसों, गन्ना, अलसी आदि प्रमुख हैं। इनमें गेहूं का रकबा सर्वाधिक है। गेहूं की उत्पादकता के लिए किए गए प्रयासों के कारण इसका क्षेत्रफल, उत्पादन तथा उत्पादकता भी तेजी से बढ़ रही है और अब मध्यप्रदेश इसके उत्पादन में अग्रणी राज्य बन गया है। इस प्रकार प्रदेश में बोई जाने वाली लगभग सभी फसलों ने विगत डेढ़ दशक में उत्पादन तथा उत्पादकता के क्षेत्र में उच्च कीर्तिमान स्थापित किए हैं। केंद्र सरकार की लोक-कल्याणकारी योजनाओं का फायदा मध्यप्रदेश को भली-भांति मिल रहा है, जिससे प्रदेश का अन्नदाता प्रसन्न और खुशहाल है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में पात्र किसानों को दावा राशि का भुगतान प्राथमिकता से कराया जाता है। योजना का लाभ दूरस्थ और गरीब किसानों को भी मिले, इसे ध्यान में रखते हुए वनग्रामों को राजस्व ग्राम में अर्थात पटवारी हल्के में शामिल किया गया है। पहले वन ग्राम राजस्व ग्राम में नहीं होने से तथा पटवारी हल्के के अंतर्गत शामिल न होने के कारण वन अधिकार पट्टों पर प्राप्त भूमि के पट्टेधारियों को फसल हानि के मामले में फसल बीमा योजना का लाभ नहीं मिल पाता था। अब सभी किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ मिलने लगा है। मध्यप्रदेश के किसानों को अपने कृषि उत्पाद निर्यात करने में सुविधा मिले तथा उन्हें अपनी उपज का अधिकतम लाभ हासिल हो सके, इसके लिए व्यवस्थागत कदमों के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। प्रमाणित एवं गुणवत्ता युक्त बीज के भंडारण के लिए पंचायत स्तर पर प्र-संस्करण इकाइयां तेजी से स्थापित की जा रही हैं। कृषि अधोसंरचना निधि के अंतर्गत मप्र को साल 2020-21 में 7500 करोड़ रुपए का आवंटन प्राप्त हुआ है, जिसके उपयोग में प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है। किसानों की आय को दोगुना करने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए आधुनिक मंडियों की स्थापना, फूड पार्क, शीत गृहों की श्रृंखला स्थापित करने के साथ-साथ साइलो एवं वेयर हाउस के निर्माण को मिशन मोड में प्रोत्साहित किया जा रहा है। नए कृषि कानूनों के आने से किसान अपनी उपज को मंडी में या अन्यत्र देश में कहीं भी बेचने के लिये स्वतंत्र हो गया है। अब जहां किसान को लाभ मिलेगा वह बिना किसी अवरोध और रोक-टोक के वहां अपनी उपज बेच सकेगा। किसान अन्नदाता एवं जीवनदाता है। कोविड-19 के संक्रमण काल में मंडियां बंद होने के कारण किसान अपनी उपज बेचने मंडियों में नहीं आ पा रहा था। प्रदेश सरकार ने कोविड-19 के संक्रमण के दृष्टिगत किसानों की भूमि उपज की बिक्री सुनिश्चित करने के लिए मंडियों से बाहर किसानों के घर से ही सौदा पत्रक के आधार पर उपज की खरीदी किया जाना सुनिश्चित किया। केंद्र की मोदी सरकार की लोक-कल्याणकारी नीतियों से किसानों के जीवन में आशातीत सुधार होने लगे हैं। पीएम-किसान योजना से किसानों के बैंक खातों में राशि सीधे ट्रांसफर होती है। यह क्रांतिकारी बदलाव है। इससे बिचौलियों की भूमिका को खत्म करने के सार्थक प्रयास किए गए हैं।

» गांवों को गोद लेंगे विश्वविद्यालय और कॉलेज » अब हर तीन महीने में देनी होगी प्रोग्रेस रिपोर्ट

# गांवों में सुधार की योजना! प्रोफेसर और विद्यार्थी देखेंगे ग्रामीण भारत

प्रशासनिक संवाददाता, भोपाल

सरकारी व निजी कॉलेज के साथ विश्वविद्यालय अपने कैंपस के पास बसे गांवों को गोद लेंगे। इसके तहत कुलपति से लेकर प्रोफेसर और विद्यार्थी गांव में जाकर ग्रामीण भारत को नजदीक से देख सकेंगे। वहां पर बदलाव का ढांचा तैयार करने के लिए कौन से संसाधनों की जरूरत है, इसकी रिपोर्ट देंगे। हर तीन महीने में इसका रिव्यू किया जाएगा। यह भी पता लगाया जाएगा कि इस दौरान क्या बदलाव आए। गांव को गोद लेने की प्रक्रिया इसी सत्र से शुरू हो जाएगी। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री का कहना है कि विश्वविद्यालयों को अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए आगे आना चाहिए और समाज के उत्थान में योगदान देना चाहिए। इसके तहत उन्हें अपने कैंपस के पास के गांव गोद लेने की योजना बनाई है। इसके लिए उन्हें अगस्त माह का समय दिया है। इस दौरान उन्हें बताना होगा कि वे कौन से गांव गोद ले रहे हैं।

## गांव की होगी पहचान

अब तक कॉलेजों में एनएसएस या एनसीसी यूनिट एक गांव का दौरा करती है। सामाजिक कार्य करती है। फिर किसी अन्य काम के लिए दूसरे गांव का चयन करती है। अब कॉलेज अपने पास के गांव की पहचान करेंगे। उसके सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए काम करेंगे। उनका काम ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं के लाभ के बारे में बताने के अलावा सामाजिक बुराइयों से अवगत कराना भी होगा।

## गोद लेने से राह होगी आसान

अब तक ग्रामीण विकास की योजनाएं एसी कक्ष या ऐसे स्थानों से बनाई जाती हैं, जिनका गांव से सीधा कोई लेना-देना नहीं होगा। आंकड़ों के आधार पर बनाई इन योजनाओं का लाभ गांव तक पहुंचने में भी एक

लंबा समय लग जाता है। योजना के बाद गांव सीधे तौर पर विकास की मुख्यधारा से जुड़ जाएंगे। अध्ययन के दौरान विद्यार्थियों को कई इनोवेटिव आइडियाज आएंगे। इनके अलावा वे गांव से जुड़े अपने आइडियाज को जमीन पर उतार सकेंगे। सीधे तौर पर किताबी ज्ञान से वे प्रेक्टिकल की ओर कदम बढ़ाएंगे। इससे उनका जुड़ाव गांव के वास्तिक परिदृश्य से हो पाएगा।

## ग्रामीणों को मिलेगा एक मंच

सड़क, बिजली, पानी जैसी समस्याओं से रूबरू हो रहे गांव के लोगों को एक मंच मिलेगा, जहां वे अपनी समस्याएं साझा कर सकेंगे। हर तीन महीने में संबंधित गांव का रिव्यू होने पर यह पता लगाने में आसानी होगी कि संबंधित गांव में इस दौरान क्या बदलाव, सुधार आए। गांव के ऐसे युवा जो आगे पढ़ाई करना चाहते थे लेकिन किन्हीं कारणों से उन्हें उसे छोडना पड़ा, योजना ऐसे युवाओं को एक बार फिर से मौका देगी। इसके तहत गांव में ही रहकर वे क्या कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं, इसका मार्गदर्शन मिलेगा। इसके अलावा उसे जमीन पर लाने में मदद भी मिलेगी।

## नजदीक से देखने का मौका

योजना की शुरुआत होने से विद्यार्थियों और प्रोफेसर्स को गांव और ग्रामीणों के बीच जाने का मौका मिलेगा। जिससे वह ग्रामीण भारत के बारे में जान सकेंगे। इसे विद्यार्थी एक बड़े मौके की तरह भी देख सकते हैं। रूरल डेवलपमेंट के अंतर्गत अपने इनोवेटिव आइडियाज को गोद लिए हुए गांव में प्रयोग के तौर पर पूरा कर सकते हैं।

## योजनाओं की रिपोर्ट बनाएंगे

गोद लेने के बाद विवि का काम होगा कि वह गांव की तरक्की के लिए अलग-अलग उपाय सोचें। उस पर काम करें। शासन की योजनाओं को गांव के हर व्यक्ति तक पहुंचाते हुए लाभ के बारे में अवगत कराएं। गांव की समस्याएं और सरकार की वह योजनाएं जो गांव तक नहीं पहुंची हो, उस पर अपनी रिपोर्ट तैयार करेंगे।

## इनका कहना है

योजना मप्र के पिछड़े गांवों में सुधार लाने के लिए है। विवि की बनने वाली रिपोर्ट के बाद प्रशासन का लक्ष्य उन कमियों को दूर करने का होगा। कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़े व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को स्टूडेंट्स को पढ़ाने पर जोर दिया जाएगा।

**-डॉ. मोहन यादव,** उच्च शिक्षा मंत्री

### जंगलों का आर्थिक मूल्यांकन करेगा आईआईएफएम

# अब पता चलेगा वनों का प्रदेश की जीडीपी में कितना योगदान

संवाददाता, भोपाल

भारतीय वन प्रबंध संस्थान प्रदेश के जंगलों का आर्थिक मूल्यांकन करेगा। इसके तहत पता लगाया जाएगा कि वनों का प्रदेश के जीडीपी में हर साल कितना योगदान होता है। साथ ही एक-एक पेड़ से जो लाभ मिलता है, उसका रुपयों में क्या मूल्य है।

वन हमें हवा, पानी, खनिज, लकड़ी, ईंधन, चारा, औषधियां सहित अन्य ईकोसिस्टम सेवाओं में कितना योगादान देते हैं, इसका सरकार अध्ययन करा रही है। यह काम एक साल के अंदर पूरा हो जाएगा। प्रदेश के सभी वन मंडलों का अलग-अलग सर्वे रिपोर्ट तैयार की जाएगी। इससे लोगों को उस क्षेत्र की वन संपदा के मूल्यों के संबंध में पता चल सकेगा। इसका फायदा यह होगा जब उस क्षेत्र में सरकार कोई उद्योग अथवा बड़े प्रोजेक्टों की कार्ययोजना बनाएगी तो पता रहेगा कि उस क्षेत्र की वन संपदा से सरकार के खजाने में प्रति वर्ष प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से कितन राजस्व आ रहा है।

## जंगल से जुड़े लोगों की अर्थव्यवस्था भी दिखेगी

अध्ययन में यह भी देखा जाएगा कि वन व वन संपदा से कितने लोगों को रोजगार मिला है, कितने लोग सीधे तौर पर वनों से जुड़कर काम कर रहे हैं और कितनों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिला है। आदिवासियों के जीविकोपार्जन में वन संपदा, जैसे फल, फूल, कंद-मूल, शहद, गोंद सहित अन्य चीजों से प्रति वर्ष कितनी आय हो रही है। सरकार आदिवासियों को ऐसे रोजगार उपलब्ध कराती तो सरकार पर इसका कितना भार आएगा।

## जंगल नहीं होने पर क्या प्रभाव होंगे

रिपोर्ट में यह भी बताया जाएगा कि जंगल नहीं होने की स्थिति में लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जंगल और पेड़-पौधों से शहर और ग्रामीण पर्यावरण पर क्या असर होगा। ग्लोबल वार्मिंग से भी जंगलों को जोड़ा जाएगा, ताकि इसका लाभ प्रदेश की सरकार को मिले। इसके बाद सरकार यह दावे के साथ किसी भी मंच पर बोल सकेगी कि कार्बन संचय से लेकर पर्यवरण संतुलन में प्रदेश के वनों का कितना योगदान है।

### कीट व्याधियों से बचाने की सलाह

# उड़द की फसल को देखने खेत में पहुंचे कृषि वैज्ञानिक

**टीकमगढ़।** कृषि विज्ञान केन्द्र टीकमगढ़ के प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉ. बीएस किरार, डॉ. एसके सिंह, डॉ. आरके प्रजापति, डॉ. एसके खरे, डॉ. यूएस धाकड़ और हंसनाथ खान द्वारा किसानों की उड़द फसल का भ्रमण कर किसानों को उड़द फसल को कीट व्याधियों से बचाने की सलाह दी गई। उड़द की फसल में पीला मोजेक विषाणु जनित रोग के लक्षण देखे गए। इस रोग को सफेद मक्खी नामक रस चूसक कीट फैलाता है। इस रोग से पत्तियों पर पीलापन बढ़ता है और सिरे की कुछ पत्तियां पूरी पीली पड़ जाती हैं, जिससे रोगी पौधे देर से परिपक्व होते हैं। इसके बचाव के लिए खड़ी फसल में इमिडाक्लोप्रिड 80 मिली अथवा ऐसिटामिप्रिड 60 ग्राम प्रति एकड़ की दर से 200 ली. पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। सरकोस्पोरा पर्णदाग रोग से पत्तियों पर गहरे भूरे धब्बे बनते हैं जिनकी बाहरी सतह लाल रंग की होती है। इसके नियंत्रण के लिए कार्बेंडाजिम की 200 ग्राम प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करें। उड़द की फसल में एथ्रेक्नोज बीमारी भी आती है। इस रोग के लक्षण फसल की प्रारंभिक अवस्था में पत्तियों एवं फलियों पर हल्के भूरे से गहरे भूरे काले रंग के धब्बे बनते हैं। इसके नियंत्रण के लिए कार्बेंडाजिम या थियोफिनेट मिथाइल 200 ग्राम प्रति एकड़ की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। उड़द मे भभूतिया रोग से पत्तियों की ऊपरी सतह पर सफेद चूर्ण जैसी वृद्धि दिखाई देती है, जिसके नियंत्रण के लिए घुलनशील गंधक 400 ग्राम या कार्बेंडाजिम 40 ग्राम प्रति एकड़ घोल बनाकर छिड़काव करें। उड़द फसल मे फलीवीटिल नामक कीट की इल्लियां शुरू में बीज पत्र तथा छोटे पौधों की पत्तियों में छेद करते हुए खाते हैं, जिससे पत्तियों पर छेद ही छेद दिखाई देते हैं। इसके नियंत्रण के लिए मिथाइल पैराथियान चूर्ण या क्लोरोपायरीफॉस चूर्ण की 8 किग्रा प्रति एकड़ के मान सुबह या शाम के समय भुरकाव करें।

# मप्र में होगी यूरिया की पर्याप्त आपूर्ति

## केंद्रीय उर्वरक मंत्री से मिलकर शिवराज ने की मांग

**भोपाल।** मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं रसायन, उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया से मुलाकात की। इस अवसर पर उन्होंने मुख्य रूप से यूरिया व खाद की आपूर्ति को लेकर बात की। मुख्यमंत्री ने मांडविया से मुलाकात के बाद कहा कि उन्होंने मप्र को यूरिया की पर्याप्त सप्लाई करने की बात कही। वहीं मंत्रालय सूत्रों के मुताबिक, मुख्यमंत्री ने मांडविया से फार्मा क्षेत्र में विस्तार के लिए प्रदेश में बल्क ड्रग पार्क और मेडिकल डिवाइसेस पार्क की स्वीकृति शीघ्र प्रदान करने का अनुरोध किया। दरअसल, 1276 करोड़ रुपए की लागत के बल्क ड्रग पार्क और 193 करोड़ रुपए की लागत के मेडिकल डिवासेस पार्क के प्रस्ताव केंद्र में स्वीकृति के लिए लंबित हैं।

# जबलपुर समेत बुंदेलखंड भयानक सूखे की चपेट में

- भोपाल और ग्वालियर में भी स्थिति अब खतरनाक
- 12 जिलों में 42 प्रतिशत, 19 जिलों में 18 फीसद तक कम बारिश
- अब तक 27.28 इंच बारिश, सावन में कोटे से 1 फीसदी ज्यादा
- भोपाल सहित 19 जिले ऐसे हैं जहां 4 से 18 प्रतिशत कम बारिश

# किसान चिंतित, 13 जिलों में सूखे के हालात

**भोपाल।** मध्यप्रदेश में मानसून की धमाकेदार एंट्री के बाद उसकी बेरुखी ने प्रदेश में चिंता के हालात पैदा कर दिए हैं। मालवा और निमाड़ पहले से ही सूखे की चपेट में थे। अब जबलपुर और बुंदेलखंड के हालात भी बिगड़ गए हैं। भोपाल, ग्वालियर, मुरैना और सागर जैसे बड़े शहरों में भी स्थिति ठीक नहीं है। यहां सामान्य कोटे से कम बारिश ने चिंता की लकीरें खींच दी है। मौसम विभाग की मानें तो अगर 10 दिन में इन इलाकों में अच्छी बारिश नहीं होती है तो हालत और खराब हो जाएंगे। हालांकि शिवपुरी, गुना, अशोकनगर और सिंगरौली में सामान्य से ज्यादा बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अभी इसी तरह मौसम रहेगा। कहीं-कहीं हल्की बौछारें पड़ सकती हैं, लेकिन प्रदेश में कहीं भी ज्यादा बारिश नहीं है। सप्ताह के अंत में एक सिस्टम के सक्रिय होने की उम्मीद है। अगर वह सक्रिय होता है, तो सूख प्रभावित क्षेत्रों में अच्छी बारिश की उम्मीद है। अगले 10 दिन मानसून के लिहाज से महत्वपूर्ण है। अगर इन दिनों बारिश होती है, तो प्रदेश की स्थिति ठीक हो सकती है।

### एक सप्ताह में बिगड़ी स्थिति

प्रदेश में मानसून की दस्तक समय से पहले हो गई थी। धमाकेदार बारिश के कारण प्रदेश में सभी जगह स्थिति ठीक थी, लेकिन कुछ इलाकों में कम बारिश के बाद भी राहत थी। इसके बाद मानसून ने जुलाई के शुरुआत में ब्रेक लिया। इसके बाद हालात बिगड़ने लगे। करीब 22 दिन तक बारिश नहीं होने से प्रदेश के कई इलाके सूखे की चपेट में आ गए। वहीं, ग्वालियर चंबल में ज्यादा पानी गिरने से बाढ़ ने तबाही मचा दी। मानसून के दूसरे ब्रेक के बाद हालात और बिगड़े। प्रदेश के औसत से ज्यादा बारिश वाले जिले भी सूखे की दहलीज पर आ गए।

### सूखने लगी फसल

प्रदेश में एक सप्ताह में प्रदेश भर में बारिश होने के बाद भी स्थिति खराब हो गई है। प्रदेश के 13 जिले सूखे की चपेट में हैं। यहां कम बारिश के कारण लोग परेशान हैं। पीने के पानी से लेकर फसलों तक के लिए पानी नहीं मिल रहा। इंदौर, धार, खरगोन, बड़वानी, हरदा, पन्ना, दमोह, कटनी, जबलपुर, सिवनी, छतरपुर, मंडला और बालाघाट लगातार सूखा झेल रहे हैं।

### यहां बारिश से आफत

जबलपुर के रास्ते से प्रदेश में मानूसन ने प्रवेश किया। शुरुआती दौर में ग्वालियर-चंबल में बारिश ने बेरुखी दी, लेकिन इसके बाद हुई बारिश ने यहां तबाही मचा दी। ग्वालियर-चंबल में 50 साल बाद इतनी भीषण बाढ़ आई। भिंड, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, विदिशा, राजगढ़, आगर-मालवा, शाजापुर, उज्जैन, मंदसौर और सिंगरौली में सबसे ज्यादा बारिश हुई है।

## नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेत्री मेधा पाटकर का दावा

# सरदार सरोवर बांध से रिस रहा पानी, खतरे में सुरक्षा

**भोपाल।** नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेत्री मेधा पाटकर ने आरोप लगाया है कि सरदार सरोवर बांध से पानी का रिसाव हो रहा है। उन्होंने दावा किया कि यह जानकारी डेम सेफ्टी पैनल की रिपोर्ट में कही गई है। यह मामला बांध की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। साथ ही निर्माण में भारी भ्रष्टाचार को उजागर करता है।

पाटकर भोपाल के गांधी भवन में मीडिया से चर्चा कर रही थीं। उन्होंने कहा कि नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण की बैठक होने वाली है। इसमें गुजरात सरकार ने प्रस्ताव रखा है कि सरदार सरोवर बांध की दीवार से बड़े पैमाने पर पानी रिसने के कारण बांध का पानी कम किया जाए। यदि इस प्रस्ताव को मंजूरी मिली तो गुजरात नहरों का संचालन शुरू कर देगा और मध्य प्रदेश में नर्मदा के जलस्तर पर बुरा असर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि अभी भी नर्मदा नदी की स्थिति बेहद खराब है। नर्मदा के आसपास के शहरों जैसे बड़वानी और कसरावद में नर्मदा का जलप्रवाह प्रभावित हुआ है। पुनर्वास और बिजली उत्पादन का लाभ मध्य प्रदेश को नहीं मिलने पर बकाया करोड़ों रुपए पर पाटकर ने बांध निर्माण के उद्देश्य पूर्ण नहीं होने का आरोप लगाया। एक अन्य मामले में उन्होंने कहा कि पीथमपुर के उद्योगों से केमिकल वाला पानी अजनार नदी में छोड़े जाने से कई जगह पानी पीने के योग्य नहीं रहा है।

नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़े देवी सिंह पटेल ने कहा कि कई जगह नर्मदा का जलप्रवाह बुरी तरह प्रभावित हुआ है। अब सवाल नर्मदा के अस्तित्व को बचाने का है। शरद सिंह कुमरे ने बांध निर्माण में भारी भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। राकेश दीवान ने कहा कि सरदार सरोवर बांध की सुरक्षा को खतरा होने से साबित हुआ है कि हम 36 साल से जो आशंका जता रहे थे, वह सच साबित हो रही है।

# दो साल पहले खरीदा 6.45 लाख टन गेहूं बेचेगी सरकार

## शर्त : खरीदार के पास मंडी लायसेंस होना अनिवार्य

विशेष संवाददाता, भोपाल

मध्य प्रदेश में दो साल पहले न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा गया छह लाख 45 हजार टन गेहूं अब सरकार बेचेगी। इसके लिए 70 लाट बनाए गए हैं ताकि छोटे व्यापारी भी निविदा प्रक्रिया में हिस्सा ले सकें। पिछले बार एक-एक लाख टन के दो लाट बनाए गए थे, जिसकी वजह से छोटे व्यापारी दौड़ से बाहर हो गए थे। खरीदार के पास मंडी लायसेंस होना अनिवार्य रखा गया है। प्रति क्विंटल आधार दर 1590 रुपए रखी गई है। पिछली निविदा में यह दर प्रति क्विंटल 1580 रुपए रखी गई थी। यह गेहूं 1840 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदा गया था। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 2019-20 में प्रदेश सरकार ने 72 लाख टन से ज्यादा गेहूं की खरीद की थी। सेंट्रल पूल में केंद्र सरकार ने 66 लाख टन गेहूं ले लिया पर छह लाख 45 हजार टन गेहूं लेने से इन्कार कर दिया था। इस गेहूं की खरीद में फंसी राशि को निकालने और गोदामों को खाली करने के लिए सरकार ने जून, 2021 में दो लाख टन गेहूं नीलाम करने की निविदा बुलाई थी।

### नन ने जारी की निविदा

इसमें एक-एक लाख टन के दो लाट बनाए गए थे और सौ करोड़ रुपए का सालाना कारोबार करने वाली कंपनियों को ही भाग लेने की व्यवस्था बनाई थी। इस प्रविधान की वजह से प्रदेश के छोटे व्यापारी दौड़ से बाहर हो गए थे, जिसका विरोध भी हुआ था। निविदा में एक ही कंपनी आईटीसी सफल हुई थी। सिर्फ एक प्रस्ताव होने की वजह से मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस की अध्यक्षता वाली साधिकार समिति ने निविदा निरस्त करके फिर से प्रक्रिया करने का निर्णय लिया था। अब राज्य नागरिक आपूर्ति निगम ने वर्ष 2019- 20 के छह लाख 45 हजार टन गेहूं को बेचने के लिए निविदा जारी की हैं। होशंगाबाद और जबलपुर से एक-एक लाख टन गेहूं बेचा जाएगा।

### सेंट्रल पूल में केंद्र ने लेने से कर दिया था इंकार

केंद्र सरकार ने इस गेहूं को सेंट्रल पूल में लेने से इंकार कर दिया था। दरअसल, तत्कालीन कमल नाथ सरकार ने जय किसान समृद्धि योजना के नाम से किसानों को प्रति क्विंटल 160 रुपए प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की थी। केंद्र सरकार ने इसे अनुबंध का उल्लंघन मानते हुए छह लाख 45 हजार टन गेहूं लेने से मना कर दिया था। सत्ता परिवर्तन के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी केंद्र सरकार से इस गेहूं को सेंट्रल पूल में लेने का अनुरोध किया था पर बात नहीं बन पाई।

### इधर, नमी के नाम पर हो रहा खेल

**इधर,** प्रदेश में वेयरहाउसों में नमी के नाम पर बड़ा खेल खेला जा रहा है। अभी हाल ही में ग्वालियर के महाराजपुरा थाना क्षेत्र में पुलिस ने राशन की दुकान का गेहूं सप्लाई का चौंकाने वाले मामले का भंडाफोड़ किया है। दुकान पर जो गेहूं के कटटे मिले वह 2021 वर्ष के हैं और वेयरहाउसों से अभी जो सप्लाई की जा रही है वह 2020 वर्ष की है। अब सवाल यह उठा कि जो सप्लाई की ही नहीं जा रही, वह कैसे बाजार में आ गई। प्राथमिक पड़ताल में पता चला कि गेहूं की खरीदी अप्रैल-मई में की जाती है और तब नमी 12 प्रतिशत रहती है और अब बारिश के समय में यह नमी का प्रतिशत बढ़कर 14 प्रतिशत तक हो जाता है, इसलिए गेहूं के दाने का वजन बढ़ जाता है। शासन की ओर से एक प्रतिशत तक वेट गेन मान्य है लेकिन हकीकत में दो प्रतिशत तक वेट गेन हो जाता है। वेयरहाउस संचालक इसी गेन किए वेट का फायदा उठाकर बढ़ा हुआ माल बाजार में बेच रहे हैं। अब खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने इसकी पड़ताल शुरू कर दी है। गौरतलब है कि महाराजपुरा थाना क्षेत्र में हाल ही में राशन की दुकानों पर पहुंचने वाले गेहूं का स्टाक पकड़ा था, इस स्टाक की जब जांच की गई तो पता चला कि यह गेहूं तो अभी राशन वितरण की दुकानों पर पहुंचाया ही नहीं गया है। वर्तमान में वर्ष 2020 के स्टाक का वितरण किया जा रहा है और यह पकड़े गए गेहूं के कट्टों पर वर्ष 2021 लिखा मिला है। इससे यह साफ हो गया कि वेयरहाउस से ही यह गेहूं बाजारों में निकाला गया है।

### मानसून की आमद से बढ़ जाता है वजन

गेहूं की सरकारी खरीदी अप्रैल-मई के माह में की जाती है और तब नमी का प्रतिशत 12 के करीब रहता है। अब मानसून के समय में नमी का प्रतिशत बढ़कर 14 तक पहुंच जाता है और गेहूं के दाने में नमी के कारण वजन बढ़ता है। इस तरह बढ़े हुए वजन का लाभ लेकर अतिरिक्त गेहूं को बाजार में बेचने का यह कारोबार सामने आया है। सरकार की ओर से एक प्रतिशत तक गेन वेट मान्य होता है लेकिन हकीकत में यह गेन वेट ज्यादा होने का फायदा वेयरहाउस उठा लेते हैं।

### एक हजार क्विंटल में 10 क्विंटल तक बचत

जिला आपूर्ति अधिकारी ग्वालियर सीएस जादौन का कहना है कि नमी के कारण जब गेहूं का वजन बढ़ जाता है तो एक हजार क्विंटल गेहूं में करीब 10 क्विंटल से ज्यादा अतिरिक्त गेहूं हो जाता है। इसी गेहूं को बाजार में बेच दिया जाता है। वेयरहाउस के इन कटटों से टैग पहले ही गायब कर दिए गए थे जिससे यह पता न चल सके कि किस वेयरहाउस का गेहूं है। इस मामले में विभाग अपने स्तर पर पड़ताल कर रहा है। गेन वेट का यह गेहूं स्टाक लग रहा है जिसे बाजारा में बेचा गया। यह वेयरहाउस से आया या समिति स्तर पर इसकी जांच की जा रही है। ट्रांसपोर्टर की सप्लाई भी मिलान कर रहे हैं।

# अधिक से अधिक फसल बीमा कराने किसानों को फायदे बताएगा कृषि विभाग

**भोपाल।** किसानों को प्राकृतिक आपदा से हुई क्षति से बचाने के लिए लागू प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत इस बार किसानों का पंजीयन कम हुआ है। अभी तक खरीफ फसलों के लिए लगभग 30 लाख किसानों का पंजीयन हुआ है। इस स्थिति को देखते हुए कृषि विभाग ने केंद्र सरकार से पंजीयन की तारीख बढ़ाने की मांग की थी, जिसे मान लिया गया है। अब 31 अगस्त तक पंजीयन होगा। किसानों को बाढ़ से हुए नुकसान के बहाने बीमा का महत्व समझाया जाएगा। वहीं, बीमा कंपनियां प्रीमियम की राशि 24 अगस्त तक जमा करा सकेंगी। पिछले साल 44 लाख से ज्यादा किसानों का फसल बीमा हुआ था। हालांकि, अभी इन्हें फसल क्षति का मुआवजा नहीं मिला है। कृषि विभाग ने तय किया है कि किसानों को बाढ़ से फसलों को हुए नुकसान के माध्यम से बीमा के फायदे समझाए जाएंगे। प्रदेश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ फसलों के लिए प्रीमियम की राशि जमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित की गई थी। किसानों के बोवनी में व्यस्त होने और अतिवर्षा की स्थिति को देखते हुए इस पहले बढ़ाकर नौ अगस्त और फिर 16 अगस्त किया गया। कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया कि बैंकों से ऋण लेने वाले किसानों की प्रीमियम राशि बैंक काट चुके हैं और अऋणी और डिफाल्टर किसानों ने बैंकों में राशि जमा करा दी है। इसके लिए अंतिम समयसीमा 16 अगस्त निर्धारित थी। किसानों के पंजीयन का काम अभी चल रहा है।

**अभी तक खरीफ फसलों के लिए करीब 30 लाख किसानों का पंजीयन**

### अगले माह मिल सकता है फसल बीमा

पिछले साल 44 लाख से ज्यादा किसानों ने खरीफ फसलों का बीमा कराया था। अतिवर्षा के कारण सोयाबीन सहित अन्य फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ था। कृषि विभाग की ओर से बीमा कंपनियों को दावे प्रस्तुत किए जा चुके हैं। इनका अंतिम परीक्षण चल रहा है। इसके बाद किसानों को बीमा राशि का भुगतान किया जाएगा।

### इनका कहना है

अधिक से अधिक किसानों का फसल बीमा कराने के लिए पंजीयन की अवधि बढ़ाने की मांग केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से की थी, जिसे मान लिया है। किसान बीमा कराने के लिए प्रेरित करने उन्हें ग्वालियर-चंबल क्षेत्र में आई बाढ़ से प्रभावित फसलों की जानकारी देकर समझाया जाएगा। पिछले साल किसानों को पांच हजार करोड़ रुपए से ज्यादा का फसल बीमा दिलाया गया था।

**कमल पटेल,** कृषि मंत्री

### प्रशासन और आरबीआई के नियमों में उलझा किसान

# तहसीलदार जमीनों का नहीं बना रहे बंधक पत्र, घट रही केसीसी लिमिट

**भोपाल।** किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) को लेकर इन दिनों किसान प्रशासन व आरबीआई के नियमों में उलझ कर पिस रहा है। कोरोना और फिर बाढ़ के कारण जहां किसान बदहवास हैं। वहीं उन्हें शासन की केसीसी योजना का लाभ भी नहीं मिल पा रहा है। दरअसल, किसानों को कृषि भूमि और उसमें होने वाली फसल के आधार पर केसीसी मिलती है। रबी व खरीफ (साल की दो फसल) के आधार पर कर्ज राशि की लिमिट तय होती है। मगर इन दिनों पांच एकड़ से कम भूमि वाले किसानों की जमीन तहसीलदार द्वारा बंधक नहीं बनाई जा रही है। जिसके कारण बैंक शाखा प्रबंधक आरबीआई की गाइडलाइन को आधार बनाकर केसीसी नहीं बना रहे हैं। बैंक अधिकारियों ने बताया कि जमीन को बंधक करने का अधिकार तहसीलदार को होता है। मगर तहसीलदारों द्वारा इन दिनों कहा जा रहा है कि पांच एकड़ से कम जमीन होने पर किसानी की जमीन बंधक नहीं करेंगे। जबकि बैंकर्स का कहना है कि आरबीआई के नियमानुसार एक लाख 60 हजार से अधिक की केसीसी होने पर जमीन बंधक करना अनिवार्य है। बैंकर्स की मांग है कि इस विरोधाभास का जल्द निराकरण किया जाए, जिससे कि किसानों की समस्या कम हो सके।

**एक लाख 60 हजार से अधिक हो जाती है लिमिट:** बैंक अधिकारियों ने बताया कि फसल व प्रति एकड़ जमीन के आधार पर केसीसी वैल्यू दर्ज की जाती है। जैसे यदि कोई किसान एक साल में धान व गेहूं की खेती करता है, और उसके पास 5 एकड़ जमीन है। तो उसकी लिमिट एक लाख 60 हजार से अधिक हो जाती है। उनका कहना है कि किसानों की जमीन 5 एकड़ से कम होने पर उसे तहसीलदार द्वारा बंधक नहीं किया जा रहा है। जिसके कारण किसान क्रेडिट कार्ड बनाने में परेशानी हो रही है। रोजाना दर्जनों किसान आते हैं, जो परेशान हो रहे हैं।

### चार माह से गरीब परेशान, शिकायत के बाद भी नहीं हो रही कार्रवाई

# आदिवासियों को नहीं मिल रहा राशन

केशव प्रसाद मौर्य, शिवपुरी

जिले के ग्राम पंचायत दबरा दिनारा शासकीय उचित मूल्य की दुकान है। जहां 4 महीने से राशन नहीं बाटा जा रहा है। जब राशन लेने गरीब आदिवासी शासकीय उचित मूल्य की दुकान पर पहुंचते हैं तो सेल्समैन राशन नहीं आया कह कर वापस लौटा देता है। इस मनमानी से आदिवासियों को खाने के लाले पड़ गए हैं। छोटे-छोटे बच्चे इधर, उधर भटकने को मजबूर हो रहे हैं। बताया जाता है कि दबरा दिनारा की जो उचित मूल्य की दुकान है, वह सहकारी समिति की दुकान है। कई बार आदिवासी सहकारी समिति के प्रबंधक खाद्य अधिकारी करेरा नायब तहसीलदार करेरा एसडीएम करेरा सभी को लिखित ज्ञापन सौंप चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी आज तक कंट्रोल संचालक पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। गौरतलब है कि मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा गरीबों के लिए तीन-तीन महीने का नि:शुल्क राशन वितरित करने के निर्देश दिए हैं। जबकि ग्रामीणों आदिवासियों को 4 महीने से राशन नहीं दिया जा रहा है।

# सोयाबीन की फसल पर किसानों ने चलाया रोटावेटर

**मंदसौर।** जिले के नारायणगढ़ क्षेत्र में हुई लगातार बारिश से खेतो में खड़ी सोयाबीन की फसल खराब होने लगी है। पीला मोजक से लेकर इल्लियों के बाद अब क्षेत्र में अफलन के कारण ने किसानों की परेशानियां बढ़ा दी है। इसके बाद अब किसान लहलहाती फसलों में अफलन के कारण पांच बीघा की फसल को नष्ट करवा दिया। वहीं गुडभेली बड़ी के किसान मनीष पटेल ने भी अपनी दस बीघा की सोयाबीन की फसल को ट्रेक्टर से नष्ट करवा दिया। खरीफ सीजन के शुरुआती दिनों में किसान अल्पवर्षा की आशंका से डरे हुए थे। सावन मास में अच्छी बारिश से किसानों की बेहतर फसल की उम्मीदों को पंख मिल गए थे, किंतु क्षेत्र में हुई लगातार बारिश ने किसानों की चिंता एक बार फिर बढ़ा दी है। ज्यादा बारिश के चलते खेतों में नमी होने के कारण ग्राम बरुजना कचनारा, हरसोल, फतेपुर, साबुखेड़ी छोटी गुडभेली सहित अंचल में किसानों के माथे फसल को लेकर चिंता की लकीरें दिखाई दे रही है। किसान बेहतर उपज के लिए उस पर हजारों रुपए खर्च कर उसे अच्छे भाव में बेचने योग्य बनाता है किंतु लगातार तीसरे साल भी प्रकृति का साथ नही मिलने से किसानों की उमीदो पर पानी फिर गया। इस वर्ष भी खेतो में नमी ज्यादा होने के कारण सोयाबीन का उत्पादन पूरी तरह प्रभावित होने से इंकार नही किया जा सकता है। किसानों ने यह भी बताया कि जहा सोयाबिन एक बीघा में 5 से 6 बोरी पैदावार होती थी वही इस बार उत्पादन लगभग आधे से भी कम रह जाएगा। पहीं मप्र कांग्रेस ने सरकार से किसानों को मुआवजा राशि देने की मांग की है।

**कांग्रेस नेताओं ने मौके पहुंच कर की मुआवजे की मांग**

### वाइल्ड लाइफ को नजदीक से जानेंगे बच्चे

# मप्र में स्कूली बच्चे पढ़ेंगे जंगलों की कहानियां

संवाददाता, भोपाल

मप्र के स्कूली बच्चों को जंगल, वनस्पति और वाइल्ड लाइफ से रूबरू कराने के लिए उनके सिलेबस में जंगलों, नेशनल पार्कों और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को शामिल किया जाएगा। ताकि, वे करीब से प्रकृति को जान सकें और वन्य जनजीवन से वे जुड़ सकें। उनको बताया जाएगा कि पर्यावरण के संतुलन के लिए पेड़ लगाना आवश्यक है। साथ ही, जंगलों की अवैध कटाई को रोकना भी जरूरी है। क्योंकि जंगल रहेंगे तभी हमारा जीवन सही तरीके से चल पाएगा। सरकार का दावा है कि बच्चों को साल में एक बार जंगलों की सैर भी कराई जाएगी, ताकि बच्चे जंगल और जानवर देख सकें। वे समझ सकें कि हमें ऑक्सीजन कैसे मिलती है। हमें पेड़ क्यों बचाने चाहिए। ये प्रैक्टिकल साल में हर स्कूल का बच्चा करके देखे, जिससे उनमें पर्यावरण के प्रति लगाव उत्पन्न हो। वह ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने के साथ-साथ उनकी रक्षा कर सके।

## पूरा जल चक्र नियंत्रित करते हैं पेड़

वन विभाग की इस पहल का बच्चों के पैरेंट्स भी स्वागत कर रहे हैं। एक स्टूडेंट के पिता एमके जैन का कहना है कि अकेला एक पेड़ कई जीवों को पनाह देता है। उन्हें जीने के संसाधन मुहैया कराता है। सबसे बड़ा काम ऑक्सीजन देने का करता है। पेड़ जल चक्र को नियंत्रित करने के अलावा सूर्य की गर्मी को सोखकर तापमान को नियंत्रित करते हैं। बारिश कराने में भी पेड़ों का अहम योगदान होता है। इसलिए बच्चों को जब शुरू से पेड़ों और जंगलों के महत्व के बारे में बताया जाएगा और जब वे खुद जंगल देखेंगे, तो प्रेरित होंगे। उन्हें भी पेड़ लगाने और बचाने की सीख मिलेगी। इसका फायदा पूरी मानवजाति को होगा।

## छोटी कक्षा से प्रेरणा मिलना जरूरी

वहीं, छात्र भी इसे अच्छी पहल बता रहे हैं। स्टूडेंट लोकेंद्र गुर्जर ने कहा कि धीरे-धीरे जंगल समाप्त होते जा रहे हैं। इससे कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन तेजी से बढ़ता जा रहा है। अभी कोरोना काल में ऑक्सीजन के महत्व को लोगों ने समझा है। लेकिन, जब छोटी कक्षा से पेड़ लगाने और पर्यावरण बचाने का पाठ बच्चों को पढ़ाया जाएगा तो वे भी जागरूक होंगे। उन्हें जंगलों की सैर कर बताया जाएगा कि पेड़ शुद्ध हवा ही नहीं बल्कि खाना और दवाइयां भी देते हैं। इससे प्रेरित होकर वे न केवल पेड़ लगाएंगे, बल्कि पेड़ों को कटने से भी बचाएंगे।

## इनका कहना है

हर सरकारी और प्राइवेट स्कूल का बच्चा वन्य प्राणी, पर्यावरण, पौधे और ऑक्सीजन के महत्व को समझ सके, इनका जनजीवन में क्या उपयोग है, ये जाने। इसके लिए मप्र में जितने भी पार्क और फोरेस्ट एरिया हैं, उनको स्कूल शिक्षा में पढ़ाना अनिवार्य किया जाएगा।

**विजय शाह,** वन मंत्री

# नीमच सोलर पार्क से 2.14 रुपए प्रति यूनिट की दर से मिलेगी बिजली

**भोपाल।** देश में सौर ऊर्जा के न्यूनतम टैरिफ में मध्य प्रदेश ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। हाल ही में नीमच सोलर परियोजना के लिए लगाई गई बोली में दो रुपए 14 पैसे प्रति यूनिट का रेट आया है। जबकि इससे पहले देश में सबसे सस्ती बिजली शाजापुर सोलर परियोजना से मिल रही थी। वहां दो रुपए 33 पैसे प्रति यूनिट का रेट मंजूर हुआ था। न्यूनतम ऑफर के आधार पर नीमच सोलर पार्क की 160 मेगावॉट की यूनिट-एक के लिए 2.14 रुपए और 170 मेगावॉट की यूनिट-दो के लिए 2.14 रुपए प्रति यूनिट पर टाटा पॉवर की टीपी सौर्या लिमिटेड का चयन हुआ है। जबकि 170 मेगावॉट की यूनिट-तीन के लिए 2.15 रुपए प्रति यूनिट दर के लिए दुबई की अल जोमेह एनर्जी एंड वॉटर कंपनी को चुना गया है।

## इनका कहना है

यह परियोजना करीब एक हजार हेक्टेयर भूमि पर 1750 करोड़ के निजी निवेश से स्थापित की जाएगी। इससे मार्च 2023 तक बिजली उत्पादन शुरू होने का लक्ष्य है। परियोजना स्थापना के दौरान करीब 2500 और परियोजना संचालन में करीब पांच सौ लोगों को रोजगार मिलेगा।

**हरदीप सिंह डंग,** नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री

# वन विभाग की नर्सरियों में खाद खरीदने पर रोक

**भोपाल।** खाद खरीदने में बड़े स्तर पर होने वाली गड़बड़ियों को रोकने के लिए वन विभाग ने इस पर रोक लगा दी है। अब विभाग की 171 नर्सरियों में स्थानीय स्तर पर वर्मी कंपोस्ट (केंचुआ खाद) तैयार किया जाएगा। इसके लिए मैदानी अधिकारी सिर्फ गोबर खरीद सकेंगे। इसे लेकर वन मुख्यालय ने निर्देश जारी कर दिए हैं। विभाग इन नर्सरियों में हर साल चार करोड़ पौधे तैयार करता है। जिसमें पौने तीन लाख घनमीटर खाद की जरूरत होती है। यह खाद जंगल, सड़क किनारे या अन्य वन भूमि पर होने वाली प्लांटेशन के दौरान पौधे लगाने में काम आता है। सामान्य वनमंडल उत्तर सागर में पिछले साल अधिकारियों ने 161 लाख रुपए की खाद खरीद ली थी। दमोह में भी खाद और मिट्टी खरीदने का मामला सामने आया था। मामले में जांच अंतिम दौर में है। जबकि जून 2021 में इंदौर जिले में भी चहेते ठेकेदार से खाद खरीदने में गड़बड़ी की शिकायत हुई है। ऐसी गड़बड़ी पर सख्ती से रोक लगाने के लिए विभाग ने तय किया है कि अब खाद नहीं खरीदा जाएगा। बल्कि नर्सरी खुद के संसाधनों से खाद तैयार करेंगी। खाद के लिए जरूरी गोबर का इंतजाम बाहर से किया जा सकता है। इसके लिए भी बाकायदा टेंडर प्रक्रिया का पालन करना होगा। ज्ञात हो कि प्रदेश में वन विभाग हर साल औसत 15 करोड़ रुपए का खाद खरीदता है। मध्य प्रदेश में 63 वनमंडल हैं। इनमें प्लांटेशन कराने के लिए जिला वनमंडल अधिकारी को खाद खरीदने के अधिकार हैं। शिवपुरी, दमोह, सिंगरौली, सागर सहित 10 बड़े वनमंडल हैं।

आवश्यकता

भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर और मुरैना से प्रकाशित

जागत गांव हमार

कृषि और पंचायत पर आधारित साप्ताहिक समाचार पत्र के लिए जिला, जनपद स्तर पर संवाददाता चाहिए।

संपर्क करें

जबलपुर, प्रवीण नामदेव-9300034195
शहडोल, राम नरेश वर्मा-9131886277
नरसिंहपुर, प्रहलाद कौरव-9926569304
विदिशा, अवधेश दुबे- 9425148554
सागर, अनिल दुबे-9826021098
राहतगढ़, भगवान सिंह प्रजापति-9826948827
दमोह, बंटी शर्मा -9131821040
टीकमगढ़, नीरज जैन -9893583522
राजगढ़, गजराज सिंह मीणा -9981462162
बैतूल, सतीष साहू-8982777449
मुरैना, अवधेश दण्डोतिया -9425128418
शिवपुरी, खेमराज मौर्य-9425762414
भिण्ड- नीरज शर्मा-9826266571
खरगौन, संजय शर्मा-7694897272
सतना, दीपक गौतम-9923800013
रीवा-धनंजय तिवारी-9425080670
रतलाम, अमित निगम-70007141120
झाबुआ-नोमान खान-8770736925

कार्यालय का पताः- लाजपत भवन प्रथम तल, आईसीआईसीआई बैंक के पास, एमपी नगर, जोन-1, भोपाल, मप्र,
संपर्क करें- 07554064144, 9229497393, 9425048589

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक अजय कुमार द्विवेदी द्वारा जय माता प्रिंटर्स, मं.नं.1, पेमदीपुरा बापू कालोनी के पास चिकलोद रोड, जहांगीराबाद, भोपाल(मप्र) से मुद्रित एवं एमआईजी 30, शिवकल्प, अयोध्या बाईपास भोपाल, मप्र से प्रकाशित। संपादक: अजय कुमार द्विवेदी, स्थानीय संपादक- **सतीश उपाध्याय, संपर्क** -9229497393, 9425048589, ईमेल:- jagatgaon.bpl@gmail.com (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल होगा)